पाँचवा-स्तम्भ

25 years CUTS International 1983 2008

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 12, अंक 1/2011

...✍ भ्रष्टाचार और गरीबी

मौजूदा समय में देश में भ्रष्टाचार और गरीबी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार का जहां बड़े पैमाने पर असर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर पड़ता दिखाई दे रहा है, वहीं लगातार बढ़ती महंगाई ने गरीबों को दो जून रोटी के लिए भी तरसा दिया है। इससे आमजन में भीतर तक एक हाहाकार सा मचा हुआ है। लेकिन ताज्जुब है, देश की बाग-डोर संभालने वाले इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार तो करते हैं, परन्तु इन समस्याओं के निपटान में उनकी स्पष्ट रुचि दिखाई क्यों नहीं दे रही?

वर्ष 2010 के आखिर में देश के विभिन्न कोनों से एक के बाद एक उच्च स्तर पर हुए कई खरबों रुपए के सनसनीखेज घोटालों पर से पर्दा उठा। जिनमें टूजी स्पेक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग सोसायटी, राष्ट्रमण्डल खेल आदि मुख्य हैं। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश से उच्च स्तर पर हुए अनाज घोटाले की खबरें भी आई, जिसमें 35 हजार से 2लाख करोड़ रुपए तक के घोटाले का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले एक दशक से चल रहे इस घोटाले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन, और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए आवंटित अनाज में जमकर हेरफेर किया गया।

उच्च स्तर पर हुए इन बड़े घोटालों ने जहां आमजन की आंखे खोल दी हैं, वहीं सत्ता में शीर्ष पर बैठे राजनेता अपना व अपने दल के नेताओं का बचाव करने और राजनीतिक रोटियां सेंकने में व्यस्त नजर आए। राजनीतिक दलों में आपसी रस्सा-कशी भी चली और लगातार 23 दिनों तक चली संसद में कोई काम नहीं हुआ?

इन घोटालों से हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरी है साथ ही राजनेताओं पर से आम लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है, जो एक नई क्रांति को जन्म दे सकता है।

इस अंक में...

- रोजगार निदेशालय बना सफेद हाथी 3
- निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की होगी जांच 5
- 'अफसरों' पर सख्ती से मची खलबली 7
- बजट में बिजली पर दिया खास ध्यान 8
- विकास और पर्यावरण में संतुलन आवश्यक ..11

उपभोक्ताओं की बेहतर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अभी भी एक सपना

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मेनेजर एस.एन.पाण्डा

हमारे देश में हर साल करीब एक करोड़ 50 लाख नये उपभोक्ता विभिन्न वित्तीय सेवाओं से जुड़ते हैं। लेकिन वित्तीय सेवाओं तक उपभोक्ताओं की बेहतर पहुंच और सामर्थ्यता की कमी अभी भी बाकी है।

उक्त विचार कट्स द्वारा 16 मार्च को 'ग्रेनिर्का' परियोजना के तहत जयपुर में आयोजित 'उपभोक्ताओं के लिए उचित वित्तीय सेवाएं' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर सर्किल के जनरल मेनेजर एस.एन.पाण्डा ने मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने रिजर्व बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने की पहल की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ताओं को सही सेवाएं और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं की सेवा प्रदाता कम्पनी तक पहुंचने में होने वाली मुश्किलों के बारे में बताते हुए कहा कि उपभोक्ताओं में अभी जागरूकता की कमी है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज बैंक एक दूसरे पर इतने आश्रित हो गए है कि यदि किसी दूसरे देश में बैंकिंग संकट आता है तो उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है।

कार्यशाला में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय जयपुर की उप मुख्य प्रबन्धक श्रीमती के. सुन्दरी ने बैंकिंग लोकपाल की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके जरिए उपभोक्ता बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। इस अवसर पर राजस्थान उपभोक्ता आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस विनोद शंकर दवे ने कानूनी क्षेत्र से जुड़े अपने निजी व पेशेवर अनुभवों को उदाहरणों के माध्यम से भागीदारों के सामने रखा और उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता के बीच के संबंधों पर चर्चा की।

बैंकिंग लोकपाल कार्यालय जयपुर के सहायक महाप्रबन्धक एस.एन. सेनापति ने सेबी, आईआरडीए व रिजर्व बैंक जैसे विनियामक संस्थाओं द्वारा वित्तीय सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को दिए जा रहे योगदान की जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में केन्द्र व राज्य के नीति निर्माताओं, मीडिया, परियोजना भागीदारों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

'जैव विविधता संरक्षण' राष्ट्रीय अभियान में सभी का सहयोग आवश्यक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 14 मार्च, 2011 को जयपुर में कट्स द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जॉर्ज चेरियन ने राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पिछले 25 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। मंत्रालय देशभर में स्वयंसेवी संस्थाओं एवं विद्यालयों के माध्यम से इसके लिए विभिन्न जागरूकता एवं भौतिक कार्य संचालित करता है।

इस वर्ष के विषय 'जैव विविधता संरक्षण' के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि मानव ही जैव विविधता संरक्षण में रुकावट पैदा कर रहा है। उन्होंने जैव विविधता के आशय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के युग में पर्यावरण के उचित संरक्षण के लिए जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियों, जलीय जीव-जंतुओं एवं कीट-पंतगें आदि सभी जैव विविधता की श्रेणी में आते हैं। इनके संरक्षण पर उचित ध्यान देना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 को 'अन्तरराष्ट्रीय वन वर्ष' घोषित किया गया है। उन्होंने अभियान से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं और विद्यालयों की ओर से कार्यशाला में उपस्थित प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि वे पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय अभियान को विभिन्न प्रकार से जागरूकता व भौतिक गतिविधियों का क्रियान्वयन कर सफल बनाएं। कार्यक्रम के दौरान परियोजना अधिकारी अमरदीप सिंह ने जैव विविधता विषय पर प्रस्तुतिकरण देते हुए जीव-जन्तुओं की विलुप्ति से पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान और उसके प्रभावों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के प्रारंभ में अभियान प्रभारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का 1986 से चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण अभियान है। कट्स संस्था राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 2006-07 से रीजनल रिसोर्स ऐजेन्सी (आर.आर.ए) के तौर पर कार्यक्रम को संचालित कर रही है। इस अभियान के तहत राज्य की स्वयंसेवी संस्थाएं और विद्यालय अपने अपने क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता अभियान की विभिन्न गतिविधियां संचालित करते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने इस वर्ष का विषय 'जैव विविधता संरक्षण' रखा है।

राज्य स्तरीय इस कार्यशाला में राज्यभर की करीब 200 प्रतिभागी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्थाओं को विषय के तहत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। जैव विविधता संरक्षण विषय पर कार्यशाला स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूर्व में अभियान के तहत की गई गतिविधियों के पोस्टर पम्पलेट व चित्र आदि प्रदर्शित किए।

कट्स-केग परियोजना के अन्तर्गत

समुदाय अंक पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

'अन्सा' के सहयोग से संचालित कट्स-केग परियोजना के तहत राज्य की चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं को समुदाय अंक पत्र विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समुदाय अंक पत्र सामाजिक जवाबदेहिता का एक ऐसा उपकरण है, जो कि सार्वजनिक सेवाओं में सुधार से सुशासन को सुनिश्चित करता है।

जनवरी से मार्च 2011 के दौरान उक्त विषय पर तीन संभाग स्तरीय कार्यशालाएं (चार दिवसीय) आयोजित की गई। उदयपुर और कोटा संभागों की संस्थाओं के लिए कार्यशाला चित्तौड़गढ़ में 10 से 13 जनवरी को आयोजित की गई, जिसमें 23 संभागियों ने भाग लिया। उन्होंने केल्जर और घोसुण्डी ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया और समुदाय अंक पत्र का वास्तविक प्रयोग करके देखा। जोधपुर संभाग की संस्थाओं के लिए जोधपुर में 2 से 5 फरवरी तक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 13 संभागियों ने भाग लिया। संभागियों ने जुड़ ग्राम पंचायत का भ्रमण भी किया।

अंतिम कार्यशाला बीकानेर संभाग की संस्थाओं के लिए चूरू में 7 से 10 मार्च तक आयोजित की गई, जिसमें 10 संभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के संभागियों ने सताड़ा ग्राम पंचायत का भ्रमण किया। परियोजना के अन्तर्गत संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजस्थान के सभी जिलों से कुल 67 संभागियों ने समुदाय अंक पत्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

रोजगार निदेशालय बना सफेद हाथी

बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए खोला गया रोजगार सेवा निदेशालय राज्य सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। राज्य सरकार जहां एक ओर सभी जिलों में कार्यरत निदेशालय के कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तनख्वाहों और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था पर हर माह एक करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करती है, वहीं निदेशालय बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने में नाकामयाब है।

हाल ही सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में खुलासा हुआ है कि रोजगार सेवा निदेशालय पिछले दस साल में मात्र 55 हजार बेरोजगारों को ही नौकरी दिलवाने में मददगार साबित हुआ है। स्थिति यह है कि पिछले साल वह एक हजार लोगों को भी नौकरी नहीं दिलवा पाया। हालात यह है कि विभाग की वेबसाइट पर देशभर की नौकरियों की भी जानकारी नहीं मिल पाती। इससे लाखों बेरोजगारों का रोजगार विभाग से मोह भंग हो गया है।

(रा.प., 25.03.2011)

जलदाय विभाग में करोड़ों का कबाड़ा

जलदाय विभाग के जयपुर शहर कार्यालय की ओर से पिछले तीन सालों में करीब 11.32 करोड़ रुपए की खरीद में अधिकारियों ने खूब कमीशन बटोरा। वित्त विभाग की निरीक्षण शाखा ने हाल ही उत्पादन और वितरण खंड की विशेष जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। जरूरत से अधिक पाइपों की खरीद, स्टॉक पंजिका में सामग्री के उपयोग का इन्द्राज नहीं होना, पाइप उपलब्ध होने के बावजूद नए की मांग व अनुपयोगी सामान का निस्तारण नहीं करना जैसी अनेक अनियमितताएं भी जांच में सामने आई हैं।

जांच में सीमेंटेड पाइपों की खरीद में भी काफी गड़बड़झाला सामने आया। रोक के बावजूद खरीदे गए लाखों रुपए के पाइप सड़कों, खाली भूखंड़ों और रेल पटरियों के किनारे बिखरे पड़े मिले। इस तरह लाखों की सरकारी सम्पत्ति कबाड़ में तब्दील हो गई। करोड़ों रुपए के इस खेल में आला अफसरों की करतूत सामने आने के बावजूद तथा पाए गए कई दोषी अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं करना विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

(रा.प., 15.02.11 से 19.2.11)

बिना आदेश खरीदा ढ़ाई करोड़ का चारा

राज्य के टोंक जिले में अकाल (2010) के दौरान किसानों को पशुओं के लिए अनुदान पर आहार उपलब्ध कराने की खरीद में दो करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति ने अजमेर व नदबई की फर्म से करीब ढ़ाई करोड़ रुपए का पशु आहार बिना क्रय आदेशों के फोन पर आदेश देकर मंगा लिया, जबकि नियमों के अनुसार तीन हजार से अधिक का सामान बिना क्रय आदेश के नहीं खरीदा जा सकता। खरीदे गए आहार का वजन भी नहीं कराया गया।

किसानों को उनके पशुओं के लिए किए गए आहार वितरण में भी प्रथम दृष्टया काफी गड़बड़ियां हैं। पशुआहार के प्राप्त बिलों और उनके भुगतान में भी फर्जीवाड़े की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए मामले की जांच के लिए कोषाधिकारी व उपजिला कलक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है।

(रा.प., 11.02.11)

एस बैंड स्पेक्ट्रम-करोड़ों का नया घोटाला!

2जी स्पैक्ट्रम घपले में घिरी केन्द्र सरकार उससे भी बड़े एक और स्पेक्ट्रम घोटाले में फंस सकती है। दरअसल, वर्ष 2005 में भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान (इसरो) की व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड व बेंगलूर की देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लि. कंपनी के बीच स्पेक्ट्रम को लेकर 20 साल का करार हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक, कैग (सीएजी) का शुरुआती आकलन है कि इस करार से सरकारी खजाने को कम से कम दो लाख करोड़ रुपए की चपत लगती दिख रही है। सीएजी फिलहाल इसकी जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि करार के तहत बिना नीलामी के एस बैंड स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय, केबिनेट को नहीं दी गई। जबकि इसरो अंतरिक्ष विभाग के तहत आता है और उसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास है। *(दै.भा.एवं रा.प., 08.02.11)*

करोड़ों की गॉज-बैंडेज सप्लाई में खेल

साधारण चोट और जख्म से लेकर ऑपरेशन आदि के घावों की ड्रेसिंग कर मलहम के काम आने वाली गॉज-बैंडेज घावों को भरने के बजाय 'हरा' कर रही है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि उनके यहां सप्लाई में आ रही गॉज-बैंडेज का स्तर काफी घटिया है। सरकारी अस्पतालों में गॉज-बैंडेज की सप्लाई राजस्थान स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लि. और बुनकर संघों से होती है।

सरकारी लेबोरेट्री में गॉज-बैडेंज का परीक्षण नहीं कराया जा रहा। निजी लैब में नमूना पास कर दिया जाता है इससे करोड़ों की सप्लाई तुरंत हो जाती है। सरकारी और निजी लैब के नतीजों पर गौर करे, तो आलाअफसरों की मिलीभगत होने की बात सामने आती है। मामले की सतही जांच हो तो कई घोटालों पर से पर्दा उठ सकता हैं।

(दै.भा., 15.02.11 एवं 22.02.11)

बिजली निगम में एक करोड़ का घपला

अजमेर बिजली वितरण निगम के जहाजपुर उपखंड में अप्रेल 2007 से सितम्बर 2010 तक 80 कनेक्शन में करीब एक करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। निगम ने नियम विरूद्ध घरेलू कनेक्शन की जगह कृषि व अघरेलू कनेक्शन जारी कर दिए। सर्विस लाइन की जगह 11 केवी लाइन खींची गई।

यह खुलासा निगम की टेक्निकल ऑडिट में हुआ है। अब जहाजपुर सहायक अभियंता ने वसूली के लिए 30 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। इस फर्जीवाड़े में निगम के एईएन और कई अन्य कर्मचारी निलम्बित भी किए गए हैं। अब मामले की रिपोर्ट सीआईडी सीबी को भिजवाई गई है।

(दै.भा., 25.03.11)

सरकार ने दिए किसानों को घटिया बीज

सरकार ने निजी फर्मो के माध्यम से किसानों को उड़द का घटिया बीज सप्लाई करवा दिया। इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और किसानों को उसका मुआवजा तक नहीं मिल रहा। बीज के घटिया होने का पता तब चला जब किसानों ने पौधे की बढ़वार अच्छी होने के बावजूद उनमें फूल और फलियां नहीं बनने की शिकायत की।

जब कृषि विशेषज्ञों ने खेतों में जाकर जांच की तो बीज घटिया होने की पुष्टि हुई। यह बीज टोंक, कोटा, बूंदी, बांरा और झालावाड़ जिलों में बांटा गया था। विभाग अब पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटा है। यह बीज कृषि विभाग की सिफारिश पर राज्य बीज निगम ने 6226 किसानों को वितरित किया था। *(दै.भा., 19.02.11)*

खुली स्वास्थ्य अभियानों की पोल

अलवर के दिनेश जैन की शिकायत पर हाल ही वित्त विभाग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अलवर की विशेष ऑडिट कराई। 2003 से 2007 तक की तीन साल की हुई ऑडिट में करीब नौ करोड़ रुपए की गड़बड़ियां उजागर हुई।

यह गड़बड़िया बताती हैं कि किस कदर स्वास्थ्य विभाग के पल्स पोलियो अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य राष्ट्रीय योजनाएं विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए ऊपरी कमाई का जबरदस्त जरिया बनी हुई हैं। चिकित्सा विभाग की इन योजनाओं में अग्रिम भुगतान दर्शा कर गड़बड़झाला किया जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा यदि अन्य जिलों में भी ऑडिट कराया जाए तो हर जिले में ऐसी कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। *(रा.प., 12.01.11)*

डॉक्टरों की शिकायतों का नहीं है रिकॉर्ड

राजस्थान मेडिकल काउंसिल में डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली शिकायतों का कोई रिकॉर्ड नहीं होने से सवालिया निशान लग गया है। यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के आधार पर हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने डॉक्टरों का पंजीकरण करने, मरीज के प्रति लापरवाही बरतने पर मिलने वाली शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए राजस्थान एक्ट 1952 के तहत इस काउंसिल की स्थापना की थी। काउंसिल के अध्यक्ष डॉ.ओ.पी. गुप्ता कहते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ होने वाली शिकायतों का रिकॉर्ड तैयार करने में समय लगेगा। रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, इसके बाद सूचना मिल सकेगी। एक दो साल का रिकॉर्ड चाहे, तो मिल सकता है। *(दै.भा., 27.03.11)*

क्यों नहीं पनपे लगाए गए पौधे?

राजस्थान में पिछले दो दशकों में हरित राजस्थान, वृक्षारोपण अभियान, वानिकी विस्तार कार्यक्रमों, हरा-भरा राजस्थान, पेड़ लगाओं सूखा हटाओ जैसे कई अभियानों के तहत करीब 70 से 80 करोड़ पौधे और वृक्ष लगाए जा चुके हैं। हर साल करीब 3 से 4 करोड़ पौधे रोपे गए। सवाल यह है कि आखिर इन वृक्षों व पौधों में से कितने पनपे और कितने पनप ही नहीं पाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि कम से कम 60 से 70 प्रतिशत वृक्ष और पौधे पनपने चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि 40 से 50 प्रतिशत पौधे ही मुश्किल से पनप पाए हैं। वृक्षारोपण और हरित राजस्थान अभियान के तहत जमकर अनियमितताएं और घोटाले हुए, लेकिन सरकार ने न तो इसकी जांच और न ही मूल्यांकन कराने की जरूरत समझी, जबकि ऐसे अभियानों को थार-मरूस्थल की चुनौतियों के मद्देनजर गंभीरता से लेना चाहिए। *(दै.भा., 17.03.11)*

प्रसूताओं की मौतों पर उठे सवाल

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 21 प्रसूताओं की एक के बाद एक हुई मौत ने राज्य सरकार की 'प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम' पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मातृ एवं शिशु मृत्युदर रोकने के लिए यह सिस्टम शुरू किया गया था। लेकिन राज्य में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी नहीं आ रही है।

इन मौतों का कारण संक्रमित ग्लूकोज, नकली दवाइयां, संक्रमित लेबर रूम व संक्रमित वातावरण पाया गया। लगातार होती रही इन मौतों के प्रति किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर राज्य सरकार, उसका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जांच तक के लिए 15-16 महिलाओं की मौतों का इंतजार क्यों करता रहा? मौतों को इतने हल्के तौर पर क्यों लिया गया? इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? *(दै.भा. 18.03.11)*

आयुर्वेद अस्पतालों में धांधली

आयुर्वेद अस्पतालों की बदहाली और वैद्यों के गायब रहने की शिकायतें जहां आम है, वहीं रजिस्टर में मरीजों की फर्जी उपस्थिति दिखा कर मुफ्त में दी जाने वाली महंगी आयुर्वेदिक दवाओं में धांधली करने के मामले भी सामने आने लगे हैं। बगरू स्थित राजकीय आयुर्वेद अस्पताल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे से यह खुलासा हुआ। मामले में वैद्य और कम्पाउंडर को मुफ्त दवा देने में हेराफेरी करने का दोषी पाया गया।

ब्यूरो की ओर से मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुर्वेद विभाग के निदेशक को लिखा गया। साथ ही राज्य के विभिन्न आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी आकस्मिक निरीक्षण कराने की बात कही गई। अमूमन रूप से यह देखा भी गया है कि राज्य के आयुर्वेदिक अस्पतालों में गरीबों के लिए आई लाखों रुपए की मंहगी दवाओं का वितरण ही नहीं किया जाता। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि महंगी दवाएं आखिर जाती कहां हैं। लेकिन विभाग ने मामले में लीपापोती कर दोषियों को दोषमुक्त कर दिया। *(दै.भा., 02.01.11)*

प्रदेश पर बढ़ता जा रहा कर्जे का बोझ

देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश पर 31 मार्च 2010 तक 91532.92 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसमें यदि चालू वित्तीय वर्ष के अनुमानित राजकोषीय घाटे की रकम जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा एक लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा।

सरकार की बिजली कंपनियों व रोडवेज की हालत और भी चिन्ताजनक है सरकार की बिजली कंपनियां 31 मार्च 2010 तक ही करीब 25000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। इसी तरह रोड़वेज भी मार्च 2010 तक करीब 797 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है। इससे प्रदेश पर कर्जे का भार बढ़ता जा रहा है। हर राजस्थानी 15255 रुपए का कर्जदार है। यह राज्य के बीमारू दर्जे का परिचायक है। *(रा.प., 22.02.11 एवं 04.03.11)*

घोटाले पर लगाया सच्चाई का ठप्पा

राज्य में बिना पैनल के विद्यालयों में सीए ऑडिट कराने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की पुष्टि हुई है। जिला परिषद के अधिकारी ने डेढ़ माह में जांच पूरी कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में जयपुर की फर्म से 25 लाख 91 हजार 476 रुपए की राशि वसूली योग्य बताते हुए, इस खेल में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े सात जिला अधिकारी, 12 ब्लॉक अधिकारी एवं लेखा शाखा के दो कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है।

जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि सीए कंपनी ने नियुक्ति आदेश प्राप्त किए बिना स्कूलों से रिकॉर्ड मंगवाया और अंकेक्षण के नाम पर वर्ष 2008-09 व 2009-10 की अंतिम प्रविष्ठि पर मात्र मुहर बिना हस्ताक्षर के लगा दी गई। जांच अधिकारी ने इस भुगतान को निरर्थक बताया है। *(रा.प., 09.02.11)*

सुशासन का शत्रु है भ्रष्टाचार

राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को विकास और सुशासन का शत्रु करार दिया है। भ्रष्टाचार की बेड़ियों से बाहर निकलने पर खास जोर देते हुए उन्होंने इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यवस्थागत बदलावों पर जोर दिया है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानों, उद्योग जगत और नागरिक समुदाय को अपने काम-काज में सुचिता के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। उन्होंने संसद को देश की संप्रभुता का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसके सुचारू संचालन का जिम्मा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में धन व बाहुबल की रोकथाम की जरूरत पर जोर दिया। *(दै.भा., 26.01.11)*

काला धन-नाम क्यों नहीं खोलती सरकार

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अवैध तरीकों से जोड़ा और विदेशों में जमा किया धन राष्ट्रीय लूट का प्रतीक है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को विदेशों में काला धन जमा कराने वाले भारतीयों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की पीठ ने बैकों में जमा काले धन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए याचिका का दायरा संकुचित करने और विदेशों में काला धन जमा कराने वाले भारतीयों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर केन्द्र सरकार की खिंचाई की।

(रा.प. 15.01.11 एवं न.ज़ु., 20.01.11)

माथे पर लगा है भ्रष्टाचार का कलंक

राज्य विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति पीड़ित है। लोगों के मानवीय मूल्य बदल गए हैं। लोग रातों रात लखपति और करोड़पति बन जाना चाहते हैं। आज राजनेता भ्रष्टाचार की कालिख से पोत दिए गए हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि कुछ ही भ्रष्टाचारियों की वजह से यह कलंक सभी के माथे पर लगता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें समाज के बुद्धिजीवियों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वे समाज को सही मूल्यों की शिक्षा दें। राजस्थान राजनीति विज्ञान परिषद के अखिल भारतीय सम्मेलन की शुरूआत करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे बड़ा दायित्व शिक्षक वर्ग का है और उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। *(रा.प., 08.01.11)*

निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की होगी जांच

निजी क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अब पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सीधे जांच और कार्रवाई करने के अधिकार मिलेंगे। किसी कंपनी या निजी उद्यम के कर्मचारी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर ब्यूरो छापामारी कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को ट्रेप कर सकेगा।

केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 ए में नई धारा 160 ए और 160 बी जोड़ने जा रही है। इसके लिए संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इसके लिए केन्द्र ने राज्य से भी राय मांगी थी, जिस पर राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। *(दै.भा., 03.03.11)*

क्या होगा असर?

निजी कंपनियों और फर्मों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए सरकारी जांच एजेन्सियों को व्यापक कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। आम आदमी निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेन्सियों के पास शिकायत कर सकेगा।

ईमानदारी पर लगा सवालिया निशान

राज्य में सालाना सौ से ज्यादा 'बड़े साहबों' की ईमानदारी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हाल ही राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी से यह सामने आया है। विधायक ओम बिड़ला के एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी तो पता चला कि तीन सालों में राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ 332 मुकदमें दर्ज हुए हैं।

ऊंचे पदों पर बैठे अफसरों के खिलाफ दर्ज इन अभियोगों में भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बावजूद मामले को अदालत तक पहुंचाने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पसीने छूट जाते हैं। तीन सालों में दर्ज इन मामलों में से 142 मामलों में 152 राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 98 मामलों में ही 104 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। *(रा.प., 15.02.11)*

चुनाव है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई.कुरैशी ने कहा है कि चुनाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत है और चुनावों के दौरान देश में पेड न्यूज की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाल ही पेड न्यूज के 86 मामले हमारे नोटिस में आए हैं।

उन्होंने कहा मीडिया घरानों और राजनीतिक दलों के बीच की संधियां परेशान करने वाली हैं। पहले यह सांकेतिक विज्ञापन होता था, लेकिन अब राजनीतिक दल और मीडिया घराने ज्यादा साहसी हो गए हैं और चुनावी घोषणा-पत्र को संपादकीय के रूप में छाप रहे हैं। यह सिर्फ अनैतिक ही नहीं बल्कि तकलीफदायक भी है और हम इस पर नजदीकी से निगाह रखे हुए हैं। *(रा.प., 27.03.11)*

सरकार काला धन उजागर करने को राजी

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया है कि वह विदेशी बैंकों में काला धन रखने वालों के नामों का खुलासा करेगी। बस, एक बार उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वह पुणे निवासी व्यापारी हसन अली को विदेश न भागने दे। अली पर विदेशी बैंकों में काला धन छिपाने के आरोप हैं।

सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली बैंच के सामने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन रखने वालों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एक बार उनके खिलाफ मामला दर्ज होते ही नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

(दै.भा., 11.02.11)

भारतीय बैंकों में भी कालाधन?

भारतीय बैंकों में भी कालाधन है? यहां ऐसे अरबों रुपए पड़े हैं, जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। यह कई सालों से बिना किसी दावे के बैंकों में जमा है। सूचना के अधिकार के तहत यह सनसनीखेज खुलासा सामने आया है।

चाही गई सूचना के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि भारतीय बैंकों में 13 अरब से भी ज्यादा ऐसे रुपए है जिन पर किसी का भी दावा नहीं है। यह करीब दस साल पुराने है। 31 दिसम्बर 2009 को बैंकों में इस तरह के 13 अरब 60 करोड़ 31 लाख 59 हजार 646 रुपए 89 पैसे बिना दावे के हैं। इसमें भारत स्थित विदेशी बैंकों में 47 करोड़ 31 लाख 67 हजार 698 रुपए और दूसरे निजी बैंकों में 15 करोड़ 3 लाख 23 हजार 106 रुपए हैं। बाकी धन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा है। *(रा.प., 09.03.11)*

शर्म से झुक जाता है सिर....

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण से चिंतित मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर लोग कहते हैं कि हमारे 543 लोकसभा सदस्यों में से 162 सदस्यों पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या, दुष्कर्म, फिरौती और भ्रष्टाचार जैसे मामले हैं और इनमें से 76 सदस्यों पर गंभीर आरोप हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है।

विडंबना है कि जेल में बंद अभियुक्त मताधिकार के लिए तो अयोग्य है, लेकिन वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए गए विधायकों और सांसदों को तत्काल अयोग्य ठहराया जाए। अयोग्य ठहराने का अधिकार संसद को है। ऐसे में सिफारिश की गई है कि गंभीर अपराधों के आरोपियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।

उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और संरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। चुनावी चंदे पर सवाल उठाते हुए श्री कुरैशी ने कहा कि नियमानुसार 20 हजार रुपए से अधिक का दान चैक से दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। *(रा.प., 10.01.11)*

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा विकास का पैसा

'विकास के लिए मिलने वाला ज्यादा पैसा निरर्थक जाने की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार है। इससे आर्थिक और सामाजिक विषमता है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हमारे विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है।'

- प्रतिभा पाटील, राष्ट्रपति

(दै.भा., 07.02.11)

चन्दे में मिलता है काला धन

'मैं चार साल से संसद में हूं, चंदा चैक के जरिए नहीं आता और न ही पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जाता है। सारी रकम काले धन के रूप में मिलती है।'

- राहुल बजाज, मशहूर उद्योगपति और सांसद

(दै.भा., 05.02.11)

कैंसर की तरह है भ्रष्टाचार

'देश की राजनैतिक-नौकरशाही-न्यायिक व्यवस्था को एक कैंसर जैसी स्थिति निगल रही है, विकास के लिए यह बहुत नुकसानदेह है। देश को इस वक्त वाकई कीमोथेरेपी की जरूरत है।'

-एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति

(रा.प., 05.02.11)

भ्रष्टाचार से शर्मसार.....

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों को लेकर चारों ओर से हो रहे प्रहारों के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार अच्छे शासन की जड़ें खोद रहा है। इससे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल हो रही है और यह हमें अपने लोगों के समक्ष शर्मिन्दा करता है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार देश के तीव्र विकास के मार्ग में बाधा है।

उन्होंने कहा संसद में न्यायिक जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की रक्षा के लिए दो बिल पेश किए जा चुके हैं। कानून बनाने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और प्रक्रियाओं को रफ्तार प्रदान करने की जरूरत है।

ऐसी प्रणालीगत व्यवस्था बनाने की जरूरत है किससे भ्रष्टाचार के मौके को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा भ्रष्टाचार के मौके घटाए जा सकते हैं। *(रा.प. एवं दै.भा., 05.02.11)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जयपुर	छीतर मल शर्मा	पटवारी, ग्राम पंचायत देवन, शाहपुरा, जयपुर	10,000	*रा.प., 05.01.11*
राजसमंद	नारायण सिंह सांदू	आयुक्त, नगरपालिका, राजसमंद	25,000	*रा.प., 05.01.11*
जयपुर	महेशकुमार विजयवर्गीय	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ, जयपुर विकास प्राधिकरण	40,000	*रा.प. एवं दै.भा., 07.01.11*
उदयपुर	महावीर सिंह परिहार	पटवारी, भल्ला का गुढ़ा, उदयपुर	15,000	*रा.प., 23.01.11*
जयपुर	रघुनन्दन मित्तल	उप प्रबंधक (लेखा) जयपुर डेयरी	5,000	*रा.प. एवं दै.भा., 29.01.11*
नागौर	विजय कुमार शर्मा	क. तकनीकी सहायक, पंचायत समिति कुचामन	10,000	*रा.प., 03.02.11*
जयपुर	भारत भूषण	अमीन जोन पांच, जयपुर विकास प्राधिकरण	9,000	*दै.भा. एवं रा.प., 04.02.11*
नागौर	सुमन कुमार पारीक	व्याख्याता, कांकरिया उ.मा. विद्यालय	8,000	*दै.भा. एवं रा.प., 04.02.11*
जयपुर	गोपाल सिंह	एएसआई, आमेर थाना, जयपुर	2,000	*रा.प.एवं दै.भा., 09.02.11*
अजमेर	श्याम सुन्दर	तहसीलदार का रीडर, भिनाय	2,000	*रा.प., 12.02.11*
बूंदी	रामेश्वरलाल कुमावत	सबइंस्पेक्टर, अजमेर क्लॉक टावर पुलिस थाना	7,000	*दै.भा., 18.02.11*
जोधपुर	सूरज प्रकाश शर्मा	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पीपाड़	1,500	*रा.प. एवं दै.न., 22.02.11*
सिरोही	दिनेश चन्द गुप्ता	अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रसारण निगम	10,000	*दै.भा. एवं रा.प., 23.02.11*
भरतपुर	सुखसिंह भिक्खीराम	सचिव, पंचायत समिति ग्राम पंचायत कमालपुरा सरपंचपति, पंचायत समिति वैर, भरतपुर	20,000	*रा.प., 09.03.11*
भीलवाड़ा	बरकत अली	चौकी इंचार्ज, दौलतगढ़ चौकी, आसींद थाना	10,500	*दै.भा., 23.03.11*
उदयपुर	हीरा लाल शर्मा	पटवारी, मादड़ी गांव, उदयपुर	3,500	*रा.प., 24.03.11*

गरीब का होगा जागृत स्वाभिमान

केन्द्र सरकार ने दूरदराज के गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने को 'स्वाभिमान' अभियान का रूप दिया है। सरकार का मानना है कि गरीब को बैंक खाता और वक्त जरूरत पर ऋण सुविधाएं मुहैया होने से उसका स्वाभिमान जागृत होगा। इस अभियान के तहत सरकार का मकसद देश के दूरदराज के 73 हजार गांवों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है। साथ ही 5 करोड़ लोगों के जीरो बैलेंस खाते खोले जाएंगे।

गरीबों को सामान्य बैंक व्यवहार व उत्पादों के लिए सहायता के अलावा सरकार बीमा, ऋण और उनके लिए बनी अन्य योजनाओं के लाभ देने के साथ-साथ खाता धारकों को सीधे सरकारी सब्सिडी भी पहुंचाना चाहती है। इन खातों में धन नहीं होने के बावजूद 500 रुपए का ओवरड्राफ्ट यानि उधारी भी मिल सकेगी। खातों को 'आधार' पहचान संख्या से भी जोड़ने की योजना है। *(दै.भा., 11.02.11)*

राशन की दुकानों का होगा निरीक्षण

अब वार्ड पंच से लेकर विधायक और सांसद तक राशन की दुकानों का विधिवत निरीक्षण कर सकेंगे। जिला रसद अधिकारियों को अब अपने जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से यह जानकारी देनी होगी कि उनके क्षेत्र के लिए कितनी राशन सामग्री आई है। उन्हें यह भी बताना होगा कि सामग्री का कितना उठाव हुआ व कितना बांटा गया है।

खाद्य विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में सभी जिला कलेक्टरों और जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण में सहयोग करें। साथ ही राशन डीलरों को भी आदेश दिया गया है कि जनप्रतिनिधि जब भी राशन की दुकान पर वितरण व्यवस्था, राशनकार्ड और हिसाब-किताब देखना चाहें उन्हें पूरी सुविधाएं दी जाए। *(रा.प.एवं दै.भा., 05.02.11)*

मिलावट के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य सरकार अलग से कानून लाने की तैयारी कर रही है। खाद्य विभाग ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही विधि विभाग को भेजा जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को जेल भेजने के अलावा भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों मिलावट रोकने के बारे में अलग से कानून बनाने के संकेत दिए थे। कानूनों में मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षकों को देने पर विचार किया जा रहा है। खाद्य सामग्री विक्रेताओं और निर्माताओं के यहां निरीक्षण के दौरान अपमिश्रण सामग्री मिलने पर भी कार्रवाई होगी। कानून में मिलावट साबित होने पर 10 साल की जेल और भारी जुर्माने के प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है। *(दै.भा., 17.01.11)*

अब हर सांसद को मिलेंगे 5 करोड़

केन्द्र सरकार ने सांसद विकास निधि की राशि पांच करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। सांसदों की लम्बे समय से चली आ रही क्षेत्रीय विकास निधि बढ़ाने की इस मांग को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि यह वृद्धि एक अप्रेल से लागू होगी। इससे सरकार पर सालाना 2370 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अब यह राशि दो करोड़ रुपए के बजाय पांच करोड़ रुपए होगी। सांसद विकास निधि में की गई इस बढ़ोतरी से अब प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष अपने क्षेत्र के विकास पर पांच करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार मिला है। इससे वे अपने-अपने क्षेत्र में विकास के ज्यादा काम करा सकेंगे। *(रा.प. एवं दै.भा., 12.03.11)*

समय पर काम की 'सरकारी गारंटी'

सरकारी दफ्तरों में जनता के छोटे-छोटे रोजमर्रा के काम जल्दी ही निश्चित समय में पूरे करने होंगे। यदि सरकारी कारिन्दे इसमें विफल रहते हैं तो उन्हें 250 से 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना पड़ेगा। साथ ही पंचायत व नगरपालिका से लेकर सरकारी कार्यालयों तक लोगों की समस्याओं की सुनवाई व उनका समयबद्ध निराकरण करने के लिए जनता को सुनवाई का अधिकार भी दिया जा रहा है।

जनता को यह कानूनी अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने 'राजस्थान लोक सेवाओं की अदायगी एवं सुनवाई की गारंटी अधिनियम- 2011 का मसौदा तैयार कर लिया है। इन प्रस्तावित कानून पर जनता की राय मांगी गई है। बाद में सरकार इसे अन्तिम रूप देकर लागू करेगी। प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी.जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी इसमें 15 सेवाओं को शामिल किया जाएगा। *(न.दु.एवं रा.प., 23.02.11)*

महानरेगा में बढ़ी मजदूरी

केन्द्र सरकार ने महानरेगा की मजदूरी में 19 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब राज्य में महानरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 119 रुपए की दर से मजदूरी मिलेगी। इससे पहले प्रदेश के श्रमिकों को 100 रुपए मजदूरी मिल रही थी।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी.जोशी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि बढ़ी हुई मजदूरी 1 जनवरी 2011 से लागू की गई है। सरकार हर साल खेतीहर मजदूरों के मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर बढ़ोतरी करती रहेगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 07.01.11)*

'अफसरों' पर सख्ती से मची खलबली

सरकारी घोषणाओं पर अमल में सुस्ती से नाराज राज्य सरकार ने नौकरशाही के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की ठानी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने करीब तीन दर्जन प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र लिख कर निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, चिंतन शिविर तथा कांग्रेस घोषणा पत्र पर अमल में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए।

जिस विभाग द्वारा अमल में किसी प्रकार से लापरवाही या ढिलाई बरती जाएगी तो उस विभाग के प्रमुख सचिव को मंत्रिमण्डल की बैठक में हाजिर होकर सफाई देनी होगी। सरकार के इस कदम से आला अफसरों में खलबली मची है और वे अमल की प्रक्रिया तेज करने में जुट गए हैं। कुछ अधिकारी इससे नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग का मुखिया तो मंत्री ही होता है उनकी बजाय मंत्री से ही क्यों नहीं पूछ लिया जाए कि अमल क्यों नहीं हुआ। *(रा.प., 14.02.11)*

हासिल करना होगा ऊर्जा स्वावलंबन

दिल्ली में आयोजित 'पावर विजन कॉन्क्लेव 2011' का उद्घाटन करते हुए पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि देश के विकास के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में स्वावलंबन हासिल करके ही हम जीडीपी विकास दर को दो अंकों में ले जा सकेंगे। इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। कॉन्क्लेव दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित किया गया था।

उन्होंने कहा हमें बिजली उत्पादन में स्पेस, नैनो, बायो, न्यूक्लीयर और सोलर पावर की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी साथ ही बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को भी बेहतर बनाना होगा। हमें 2030 तक हर हाल में ऊर्जा स्वावलंबन हासिल कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि न्यूक्लीयर पावर की लागत को थोरियम आधारित रिएक्टर की स्थापना करके कम किया जा सकता है। विंड पावर के लिए विंड टरवाइन, सोलर के लिए नैनो और बायोफ्यूल के लिए फ्यूल टेक्नोलॉजी विकसित करके खर्च में कमी लाई जा सकती है। *(दै.भा., 21.01.11 एवं 22.01.11)*

बजट में बिजली पर दिया खास ध्यान

बजट में राज्य सरकार ने विद्युत पर खासा ध्यान देते हुए 12067 करोड़ रुपए का बिजली क्षेत्र में प्रावधान रखा है, जो कुल बजट का 42.40 प्रतिशत है। बिजली कम्पनियों में अगले दो वर्ष में करीब 8500 नये पदों पर भर्ती होंगी। 1860 मेगावाट बिजली सरकारी क्षेत्र में व 810 मेगावाट निजी क्षेत्र में उत्पादित की जाएगी।

किसानों को 65 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। विद्युत हादसे में मृत्यु पर 2.5 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान बजट में है। बिजली के उपभोग पर प्रति यूनिट लगने वाला नगरीय उपकर 5 पैसे बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट अब 10 की जगह 15 पैसा उपकर चुकाना पड़ेगा। अलबत्ता यह भार उन शहरी लोगों पर पड़ेगा जो प्रतिमाह 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करेंगे। *(रा.प. एवं दै.भा., 10.03.11)*

खपाए घटिया ट्रांसफार्मर

विद्युत वितरण निगम में कमीशनखोरी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में घटिया ट्रांसफार्मरों से बिजली छीजत बढ़ने का मामला सामने आया है। मामले की जांच में चार निजी कंपनियों से आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मरों में गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है। ये कंपनियां ट्रांसफार्मर में कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल व कम गुणवत्ता का माल उपयोग कर गड़बड़ी कर रही थीं।

जानकारों का कहना है कि प्रदेश में रबी की फसल के मद्देनजर विद्युत वितरण निगम ने करीब आठ हजार ट्रांसफार्मर खरीदे। इनमें अधिकारियों ने आपूर्तिकर्ताओं से मिलीभगत कर ग्रामीण क्षेत्रों में घटिया ट्रांसफार्मर लगा दिए गए, जिससे छीजत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मामला खुलने पर अब अधिकारियों और कंपनियों में खलबली मची हुई है। *(रा.प., 15.02.11)*

कागजों में दिखाए जाते रहे कनेक्शन

राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के तहत प्रदेश के बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने की सरकारी योजना में लगे ठेकेदारों ने घोटाले करना शुरू कर दिया है। ऐसा एक घोटाला हाल ही धौलपुर में सामने आया है। योजना के तहत पिछले चार सालों से प्रदेशभर की ढाणियों में विद्युत तंत्र स्थापित कर कनेक्शन दिए जा रहे है।

धौलपुर जिले में 113 गांवों के 17284 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने के लिए कानपुर की कम्पनी डी कन्ट्रोल एंड इलेक्ट्रिक को ठेका दिया गया था। इस कम्पनी ने जमकर अनियमितताएं बरती। ढाणियां रोशन नहीं हो सकी और कागजों में कनेक्शन दिखाए जाते रहे। जांच में सामने आया कि 17284 की जगह मात्र 4111 बीपीएल परिवारों को ही कनेक्शन जारी किए गए। मामले की जांच जारी है। *(रा.प., 25.03.11)*

रेतीले धोरों में सूरज से बिजली

उत्तर पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में सूरज की रोशनी से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होगी। प्रदेश के झुंझुनूं से लेकर जैसलमेर जिले तक के क्षेत्र में स्पेशल सोलर एनर्जी जोन विकसित होगा। तीन सालों के दरम्यान इस क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर कुल 594 मेगावाट की सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की कई इकाइयां स्थापित होंगी।

इस सोलर जोन में पूरा जैसलमेर व बीकानेर जिला, नागौर का खिंवसर और जोधपुर का फलौदी क्षेत्र भी शामिल है। इतनी बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होने से प्रदेश बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यहां पर सोलर थर्मल पावर की आठ इकाइयां स्थापित की जाएगी, जिनमें पांच बड़ी इकाइयां होंगी। इन इकाइयों से 430 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। *(दै.भा., 21.02.11)*

आम उपभोक्ता पर डाला सारा बोझ

राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम की नाकामयाबी और लापरवाही का सारा बोझ प्रदेश के आम विद्युत उपभोक्ताओं पर डाल कर बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने का उपाय किया है। उत्पादन निगम के चार बिजलीघर निर्धारित तिथि से एक से डेढ़ साल की देरी से शुरू हुए और किसानों को बिजली देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा की महंगी बिजली खरीद ली।

आम उपभोक्ता को तो छीजत कम होने से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। इसके बावजूद सरकार ने आम उपभोक्ताओं पर 55 पैसे से एक रुपए प्रति यूनिट दर बढ़ाने की मंजूरी दे दी। दिलचस्प तथ्य तो यह है कि जो आम आदमी सबसे कम बिजली का उपयोग कर रहा है, उसे ही निशाना बनाया गया है। *(रा.प., 13.01.11)*

किसानों के लिए नहीं होगी बिजली महंगी

किसानों के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से किए चुनावी वादे को दोहराते हुए कहा कि वे अपने कार्यकाल में किसानों के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने देंगे।

राज्य सरकार ने साढ़े दस लाख कृषि उपभोक्ताओं की भविष्य में विद्युत दरें नहीं बढ़ने देने के लिए 223 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुदान की तैयारी कर ली है। सरकार किसानों के साथ बीपीएल व गरीबों को भी अनुदान देकर राहत देगी। उन्होंने संकेत दिया कि कि आगामी बजट में बिजली को प्राथमिकता दी जाएगी। *(रा.प., 13.01.11 एवं दै.भा. 27.02.11)*

जल नियामक प्राधिकरण का होगा गठन

राज्य के बजट में जल संसाधन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में जल संसाधन बेहद सीमित हैं। प्रदेश में जल उपलब्धता घट रही है वहीं बढ़ती जनसंख्या और जीवनशैली में आए बदलाव से पानी की मांग में लगातार बढोतरी हो रही है। इससे पानी की मांग और आपूर्ति में असंतुलन हो गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास उपलब्ध जल का संरक्षण कर आपूर्ति बढ़ाने के अलावा बेहतर प्रबंधन से मांग में कमी लाने का है। इस उद्देश्य से अगले साल राजस्थान जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। इसके अलावा राजस्थान भूजल नियंत्रण व प्रबंधन कानून भी बनाने की योजना है।

(न.ज्यु., 10.03.11 एवं दै.भा., 17.03.11)

अति दोहन से भूजल स्तर में आई गिरावट

अतिदोहन व सरकारी लापरवाही के कारण अवैध ट्यूबवेलों पर अंकुश नहीं लगने से जयपुर में भूजल पाताल में पहुंच गया है। पिछले छह सालों में जयपुर और आस-पास के भूजल स्तर में 26 मीटर तक की गिरावट आई है। भूजल स्तर की इस गिरावट से हर साल जलदाय विभाग के 50 से भी ज्यादा ट्यूबवेल दम तोड़ देते हैं। भूजल अब जमीनी चट्टानों तक पहुंच गया है। फलस्वरूप पानी में फ्लोराइड, क्लोराइड कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा व कठोरता बढ़ गई है। इससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

भूजल में लगातार आ रही गिरावट को ग्राउंड वाटर कंट्रोल एक्ट बना कर रोका जा सकता है। इस एक्ट में पानी को बर्बाद करने वालों पर जुर्माना और कड़ी कार्रवाई के प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। साथ ही घरों और दफ्तरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्टोर बनाकर पानी को जमीन में उतारा जाना चाहिए।

(दै.भा., 24.03.11)

समान प्रेशर से होगा पेयजल वितरण

शहर में समान प्रेशर से पानी वितरण के लिए राज्य में पहली बार रिमोट सेंसिंग प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगाए जाएंगे। रिमोट सेंसिंग प्रेशर कन्ट्रोल वॉल्व पानी के प्रेशर को समान रखेंगे। जिस समय पानी की खपत अधिक होती है, सामान्य तौर पर उस समय प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन रिमोट सेंसिंग प्रेशर कन्ट्रोल से ऐसा नहीं होगा। खपत अधिक होने पर प्रेशर कम होते ही सेंसर वॉल्व को सूचना देगा और वॉल्व से बढ़े हुए प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकेगा।

इसकी सबसे पहले शुरुआत उन क्षेत्रों से होगी जहां 24 घंटे पानी मिल रहा है। इसके बाद जोनवार शुरुआत की जाएगी। जलदाय विभाग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है जिसकी स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। *(रा.प., 04.01.11)*

जरूरी है पानी की बचत पर ध्यान देना

पानी ऐसी चीज है जिसे पैदा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी बचत पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि खेत का पानी खेत में व गांव का पानी गांव में रहे। प्रदेश के लिए पेयजल की सुचारू व्यवस्था करना सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात जोधपुर के डिगाड़ी गांव में 18 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से पुनर्गठित जलप्रदाय योजना का शुभारम्भ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जोधपुर की जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 740 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, इससे लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सकेगा। *(दै.भा., 14.02.11)*

पानी की है हर बूंद उपयोगी

विश्व जल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों, सरकारी, सेवाभावी संगठनों तथा समाजसेवियों से पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग करने की अपील की है।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में देश के उपलब्ध पानी का मात्र एक प्रतिशत सुलभ है। इसमें से भी 83 प्रतिशत पानी खेती में उपयोग आ रहा है। हर साल प्रदेश में 2 मीटर की दर से भूजल स्तर नीचे जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल के अपव्यय को रोकने के साथ ही बूंद-बूंद पानी का सदुपयोग करने के प्रति कृत संकल्प है। पानी के महत्व को देखते हुए प्रदेश में हर नागरिक को जल के संरक्षण, भूजल के पुनर्भरण और सदुपयोग के प्रति जागरूक होना होगा। *(दै.भा. एवं रा.प., 22.03.11)*

हर घर में लगे जल पुनर्भरण तकनीक

भूजल वैज्ञानिकों ने जयपुर शहर के घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल का आकलन कर निष्कर्ष निकाला है कि यदि इन घरों में जल पुनर्भरण तकनीक लगा दी जाए जो साल भर में 32 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी भूजल भण्डारों में जा सकता है। उनका कहना है कि घर-घर में वर्षा जल का संग्रहण किया जाएगा तभी जयपुर की प्यास बुझाई जा सकती है।

भूजल वैज्ञानिकों के अनुसार जयपुर को पानी पिलाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही एकमात्र उपाय है। इस सिस्टम के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल विभाग, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र में स्थित दफ्तरों में निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाता है।

(रा.प., 10.01.11 एवं 26.03.11)

कैसे रुकेगी पानी की बर्बादी

शहर में आबादी बढ़ने के साथ ही पानी का दोहन बढ़ा है। सरकारी घोषणाओं के बावजूद वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बने, जिससे भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। अब हालात विकट होते जा रहे हैं। जलदाय विभाग द्वारा खोदे जा रहे ट्यूबवेल भी फेल हो रहे हैं। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए सरकार को ग्राउंड वाटर कंट्रोल एक्ट बनाकर पानी का अपव्यय रोकना होगा। *(दै.भा., 24.03.11)*

नलकूपों से वितरित पानी का नहीं हिसाब

जयपुर शहर में खुदे सरकारी नलकूपों से जनता को कितना पानी मिल रहा है और किस नलकूप से कितना पानी उत्पादित हो रहा है इसका कोई हिसाब ही नहीं रखा जा रहा। अधिशासी अभियंता स्तर पर काफी समय से सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। हर माह एक आंकड़ा तय होता है और उसके आसपास के अंक रोजाना रजिस्टर में दर्ज कर लिए जाते हैं।

जयपुर में ज्यादातर सरकारी नलों पर उत्पादन का आंकड़ा नापने के लिए मीटर ही नहीं लगे। जिन जगहों पर मीटर लगे हैं वहा रोजाना मीटर रीडिंग ही नहीं ली जा रही। आला अधिकारियों का तर्क है कि इस काम के लिए अभी कर्मचारी नहीं है। जलदाय विभाग जयपुर क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि नई व्यवस्था अगले माह से लागू कर दी जाएगी। *(रा.प., 07.01.11)*

बुजुर्गों व महिलाओं को खास राहत

केन्द्र सरकार ने 60 साल के नागरिक को वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में माना है, इससे 60 साल के नागरिक की आयकर छूट सीमा अब 2 लाख 50 हजार रुपए हो गई है। पहले 65 साल की उम्र होने पर वरिष्ठ नागरिक माना जाता था। अब 60 साल से अधिक आयु के नागरिक को वरिष्ठ नागरिक की सभी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। राज्य सरकार ने भी अपने बजट में 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों को रोडवेज बसों के किराए में 30 फीसदी की रियायत दी है।

विधवा व परित्यक्ता महिलाओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सम्बल योजना लागू की गई है। ऐसी महिलाओं को निःशुल्क बीएसटीसी एवं बीएड प्रशिक्षण मिलेगा। छात्राओं के लिए साइकिल योजना अब कक्षा 9 से लागू की गई है। महिला स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए जहां 45 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है , वहीं साथिनों और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है। *(रा.प.एवं दै.भा., 10.03.11)*

महिला सशक्तिकरण के लिए ऋण

महिला सशक्तिकरण के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की ऋण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 50 हजार रुपए तक के दीर्घकालीन सहकारी ऋण दिए जा रहे हैं। इस ऋण से महिलाएं अपना खुद का छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर हो सकती है। वे इस ऋण का उपयोग हस्तशिल्प जैसे ग्रामीण उद्योगों और पशुपालन के लिए कर सकती हैं।

महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए बैंक द्वारा महिला विकास ऋण योजना संचालित की जा रही है। यह सहकारी ऋण दो व्यक्तियों की जमानत देने पर मिलता है। योजना के तहत राज्य के सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से महिलाओं को 5 से 50 हजार रुपए तक के ऋण दिए जा रहे हैं और इन्हें आसान किश्तों में चुकाने की सुविधा भी है। *(दै.भा., 09.03.11)*

जरूरी है योजनाओं की जानकारी

महिला जनप्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। तभी वे इसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचा सकेंगी। यह विचार पंचायती राज मंत्री भरत सिंह ने एकल नारी शक्ति संगठन के राज्य स्तरीय सम्मेलन के समापन समारोह में व्यक्त किए।

उन्होंने कहा गांवों में ज्यादातर लोगों को सरकारी योजनाओं और कानूनों की जानकारी नहीं होती इससे वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इनमें ज्यादातर महिलाएं होती है। चुनी गई महिला जनप्रतिनिधियों को उन तक जानकारी पहुंचा कर उन्हें लाभान्वित करने की दिशा में भी काम करना होगा। इस अवसर पर सम्मेलन में भाग ले रही महिलाओं ने भी उन्हें कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी दी। *(रा.प., 04.02.11)*

'छोटू' को ढूंढेगी सरकार

प्रदेश में लाखों बच्चे ऐसे है जो गरीबी और अशिक्षा के चलते ढाबों, दुकानों और कारखानों आदि स्थानों पर काम-धंधे में लगे हुए हैं। सुबह से रात तक ये कप-प्लेट धोने, झाडू-पौंछा लगाने आदि कामों मे लगे रहते हैं। इसके बदले इन बच्चों को सिर्फ दो वक्त का खाना व कुछ धन राशि दी जाती है। इसके साथ ही इन बच्चों का मालिकों द्वारा शोषण और उन पर जुल्म भी ढाए जा रहे हैं।

बालश्रम की चक्की में पिसकर अपना बचपन खो रहे ऐसे बच्चों की खोज-खबर लेने और उनके पुर्नवास के लिए सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। श्रम विभाग द्वारा कराए जाने वाले इस सर्वेक्षण में पहले उन सत्रह जिलों को शामिल किया गया है, जो काफी पिछड़े हुए हैं। इसके बाद बाकी जिलों में सर्वे कराया जाएगा। *(रा.प., 31.01.11)*

स्वास्थ्य केन्द्र 24 घंटे खुले रहेंगे

प्रदेश में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों व प्रसूताओं को चौबीसों घंटे चिकित्सा एवं प्रसूति सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य केन्द्र 24 घंटे खुले रहेंगे और उनमें चिकित्साकर्मी आवश्यक रूप से मौजूद रहेंगे। बुलाने पर डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। चिकित्सा सुविधाओं की आकस्मिक जांच भी होगी। इसके लिए राज्य स्तर पर आकस्मिक निरीक्षण दलों का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ.समित शर्मा ने चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी है। यदि कोई स्वास्थ्य केन्द्र बंद पाया गया तो संबन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदार होंगे। *(रा.प., 07.03.11)*

बाल विवाह हुए तो एसडीओ होंगे जिम्मेदार

प्रदेशभर में आखा तीज 6 मई, 2011 को बाल विवाह न हों, इसकी निगरानी और प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी कलेक्टरों और एसपी को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टरों व एसपी को भेजे पत्र में निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करें, साथ ही सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करें।

पत्र में सभी कलेक्टरों, एसपी और डीएसओ कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित करने व 24 घंटे क्रियाशील रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश हैं। पत्र में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी क्षेत्र में बाल विवाह होने पर अधिनियम के तहत उस क्षेत्र में नियुक्त बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारियों (एसडीओ) की जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। *(दै.भा., 22.03.11)*

सरपंच कोअच्छे काम पर मिला सम्मान

नरेगा में सर्वश्रेष्ठ कार्य वाली भीलवाड़ा जिले की आसींद पंचायत समिति की रामपुरा ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्रदान किया। रामपुरा देश की उन 10 ग्राम पंचायतों में शुमार है जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है।

नरेगा के पांच वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह पुरस्कार पूर्व सरपंच नंदूदेवी गुर्जर को दिया। राजस्थान से पुरस्कार के लिए दो पंचायतों का चयन हुआ था। दूसरी बांसवाड़ा जिले की बड़वास छोटी ग्राम पंचायत है। *(दै.भा., 03.02.11)*

सड़क सुरक्षा

मोटर वाहन अधिनियम-2011

वाहन निर्माताओं को खोलने होंगे ड्राइविंग स्कूल

ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने, यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई, वाहन रजिस्ट्रेशन व जांच और ओवरलोडिंग में कार्रवाई के नियमों में जल्द ही बड़ा फेरबदल होगा।

> **यह होंगे बदलाव**
>
> 18 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। व्यावसायिक लाइसेन्स लेने के लिए 20 वर्ष उम्र और 8वीं पास होना अनिवार्य। वर्ष 2015 से न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास। लाइसेंस की बनेंगी 8 श्रेणियां।
>
> ओवर लोडिंग पर न्यूनतम जुर्माना 10 हजार रुपए। गलती पर लाइसेंस निलम्बन के प्रावधान जैसे और भी कई बदलाव किए जा सकेंगे।

व्यावसायिक व सामान्य लाइसेंस के लिए स्कूल में ड्राइविंग प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। अब प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र हासिल करने वालों को परिवहन कार्यालय में लाइसेंस लेने के लिए वाहन चलाने की ट्रायल भी नहीं देनी होगी। वर्ष 2015 से सोसायटी ऑफ इंडियन मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के फिटनेस सेन्टर पर हर वर्ष फिटनेस निरीक्षण जरूरी होगा।

ये सिफारिशें मोटर वाहन अधिनियम-2011 बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले गठित सुन्दर कमेटी ने की हैं। केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित इस दस सदस्यीय कमेटी ने 402 पेज की रिपोर्ट में माना है कि वाहन चालकों का सही प्रशिक्षण नहीं होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

(रा.प., 10.02.11)

पर्यावरण

विकास और पर्यावरण में संतुलन आवश्यक

आज जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए चुनौती बने हुए हैं। औद्योगिक विकास, सोच में बदलाव और जागरूकता का अभाव पर्यावरण बिगड़ने का खास कारण है। इसे रोकने के लिए सतत विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह विचार जयपुर में आयोजित जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए विज्ञान आधारित नीतिगत विकल्प विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का उद्‌घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण नीति को कागजों में से निकाल कर जनता तक पहुंचाना अहम काम है।

राज्य सरकार सतत विकास के साथ पर्यावरण संतुलित बना रहे इसके लिए अच्छे सुझावों को लागू करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्यावरण नीति 2010 बना दी, पर इसे बनाना और लागू करना और हकीकत में बदलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध, क्लीन मैकेनिज्म सेल जैसे पर्यावरण सुधार के कदम उठाए, लेकिन जब जनता इन पर अमल करेगी तभी इसका फायदा आमजन को दिखाई देगा।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री रामलाल जाट ने कहा कि प्रदेश में 187 किमी.वन क्षेत्र बढ़ा है। पर्यावरण सुधार तभी संभव है जब सरकार के ग्रीन राजस्थान के नारे को हर आदमी अमल में लाए। आज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से राजस्थान भी अछूता नहीं है। कार्यशाला में वन व पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वी.एस. सिंह, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव डॉ. डी.एन.पाण्डे आदि ने भी अपने विचार रखे। *(रा.प. एवं दै.भा., 25.02.11)*

दूरसंचार सेवाएं

बिना नंबर बदले ऑपरेटर बदलने की सुविधा

देश में मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बिना नंबर बदले ऑपरेटर बदलने की सुविधा शुरू हो गई है। अब सिर्फ एक बार 19 रुपए अदा कर उपभोक्ता किसी भी नेटवर्क की सेवा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस सुविधा का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आएगी। जब भी इस तरह की होड़ होती है तो इसके नतीजे बेहतर रहते हैं।

उपभोक्ता जिस कंपनी की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उस कंपनी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हो और बदलना चाहता है तो बदल सकते हैं। वह अगर यह भी चाहते हैं कि उसके नंबर न बदले तो इस सेवा के शुरू होने से यह भी मुमकिन है। उन्हें सिर्फ एक बार 19 रुपए जमा कराने होंगे। बाद में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। नई कंपनी चाहे तो इस शुल्क में छूट भी दे सकती है। लेकिन एक बार मोबाइल कंपनी बदलने के बाद आप 90 दिन तक नई कंपनी की सेवाएं नहीं ले सकेंगे। समय सीमा खत्म होने के बाद उपभोक्ता फिर 19 रुपए खर्च करके नई कंपनी चुन सकता है। *(रा.प. एवं दै.भा., 21.01.11)*

निवेशक शिक्षा

प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान

'कट्स-कार्ट' जयपुर द्वारा संचालित प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 'सेबी' मुम्बई के सहयोग से आठवें दौर की दूसरी, तीसरी और चौथी कार्यशाला क्रमशः 18 जनवरी को अधाना पैलेस, धौलपुर में 24 जनवरी को श्री कल्याण टीटी कॉलेज, रेनवाल जयपुर में तथा 21 फरवरी 2011 को अहिंसा टीटी कॉलेज भानपुरकला, जयपुर में सम्पन्न हुई।

इन कार्यशालाओं में सेबी अधिकारियों, प्रतिनिधियों के अलावा प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी रखने वाले क्षेत्रीय विशेषज्ञों, बैंक व बीमा विभाग के अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा 'कट्स' प्रतिनिधियों द्वारा कार्यशाला में उपस्थित संभागियों को बचत के महत्व, विभिन्न बचत योजनाओं, सुरक्षित निवेश, आर्थिक योजना बनाने की विधि, प्रथम व द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद, म्युचुअल फण्ड व बॉण्डस आदि के बारे में जानकारी कराई गई। विषय विशेषज्ञों ने बताया कि वे 'सेबी' को प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित अपनी शिकायतें किस प्रकार दर्ज करा सकते हैं।

मानक सेवा

भारी पड़ा बैंक को खाते का लेन-देन रोकना

बैंक लोकपाल ने एक मामले में बैंक को अपने ही एक पूर्व कर्मचारी के खाते से लेन-देन रोक दिए जाने का दोषी माना और इस कृत्य के चलते ग्राहक को हुए नुकसान के लिए बैंक पर 5000 रुपए का जुर्माना मंजूर किया है।

इस मामले में बैंक के पूर्व कर्मचारी ने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि बिना किसी पूर्व सूचना के उसके बचत खाते से लेन-देन रोक दिया गया। इसके चलते उसके द्वारा जारी किया गया चैक भी अनादरित हो गया।

बैंक की ओर से उत्तर दिया गया कि ग्राहक का खाता डी-फ्रीज हो गया था, लेकिन बैंक ने यह नहीं बताया कि उसे डी-फ्रीज क्यों किया गया और यह किसके आदेश पर किया गया। लोकपाल ने माना कि खाता फ्रीज करने से पहले ग्राहक को नोटिस न भेजा जाना और बाद में चैक अनादरित कर देना यह दोनों कृत्य बैंक के सेवादोष की श्रेणी में आते हैं। इस सेवादोष के कारण लोकपाल ने बैंक को 5000 रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। *(न.ज्यू., 25.03.11)*

उपभोक्ता फैसले

शादी में नहीं पहुंची डांस पार्टी

गांव कल्लू का पुरा, तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर निवासी नारायण सिंह परमार ने ठाकुर जागरण एण्ड डांस पार्टी, धौलपुर के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच, धौलपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि अपने एक रिश्तेदार के लड़के की शादी के अवसर पर, मुरेना जिले के गांव गांगोली में 27 जून 2010 को कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उक्त डांस पार्टी को 14 हजार रुपए में बुक किया था। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र नरोत्तम के माध्यम से 2000 रुपए अग्रिम भी दे दिए थे। गांव में डांस पार्टी के कार्यक्रम के लिए शामियाना भी लगाया गया जिसका खर्च 5000 रुपए आया। लेकिन डांस पार्टी उक्त तारीख को शादी में नहीं पहुंची। इससे उन्हें रिश्तेदारों व गांव वालों से काफी भला-बुरा सुनना पड़ा।

मामले की सुनवाई पर प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर मंच ने डांस पार्टी को सेवाओं में कमी का दोषी माना। मंच ने डांस पार्टी के प्रबन्धक को आदेश दिया है कि वह श्री परमार को अग्रिम ली गई राशि 2000 रुपए, शामियाना खर्च के 5000 रुपए तथा मानसिक परेशानी व परिवाद खर्च के 1000 रुपए कुल 8000 रुपए अदा करे। मामले की पैरवी सामाजिक विकास समिति, अतरसूमा, धौलपुर के अध्यक्ष राकेश कुमार परमार ने की।

रेलवे ने लिखा 'महिला' को 'पुरुष'

महिला यात्री जेतू कंवर ने रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दर्ज कराया। अपने परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि उसने जोधपुर से हरिद्वार की यात्रा के लिए आरक्षण करवाया था।

रिजर्वेशन फॉर्म में उनके द्वारा महिला लिखने के बावजूद आरक्षण खिड़की पर रेलवे कर्मचारी ने आरक्षित टिकट में पुरुष लिख दिया। यात्रा के दौरान सही स्थिति बताने के बावजूद टीटीई ने उनसे जुर्माना वसूल लिया।

मंच ने सुनवाई पर पाया कि महिला द्वारा भरे गए फार्म में उनके नाम के आगे महिला लिखा गया था। टीटीई को नाम पर भी गौर करना चाहिए था। मंच ने रेलवे को दोषी माना और जेतू कंवर के पक्ष में फैसला दिया। अपने फैसले में मंच ने रेलवे को 25 हजार रुपए बतौर हर्जाना और 3 हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में जेतू कंवर को अदा करने के आदेश दिए।

रेलवे ने राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर सर्किट बैंच में अपील दर्ज कराई। राज्य आयोग ने सभी तथ्यों पर गौर करते हुए अपील को खारिज कर दिया और जिला मंच के फैसले को सही ठहराया। अब रेलवे को मंच के निर्णयानुसार 28 हजार रुपए बतौर हर्जाने व परिवाद व्यय के अदा करने होंगे। *(दै.भा., 19.02.11)*

नहीं मिला बिजली कनेक्शन

अमूमन रूप से शहरी क्षेत्र में शुल्क जमा कराने के बाद उपभोक्ताओं को जहां तुरत-फुरत बिजली कनेक्शन मिल जाता है, वहीं एक महिला उपभोक्ता ऐसी भी थी जिसे बिजली का कनेक्शन देने में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने दस साल लगा दिए।

हारकर झोटवाड़ा निवासी सुन्दर देवी बुनकर ने उपभोक्ता मंच, जयपुर में विद्युत वितरण निगम के खिलाफ परिवाद दर्ज कराते हुए मंच के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बिजली कनेक्शन के लिए निगम कार्यालय में शुल्क जमा कराने और बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें दस साल तक बिना बिजली के रहना पड़ा है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक, अधीक्षण अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को सेवा में कमी का दोषी माना। मंच ने यह भी माना कि समय पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से उपभोक्ता को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। अतः मंच ने जयपुर विद्युत वितरण निगम को आदेश दिए कि वह सुन्दर देवी बुनकर को हुए मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के तौर पर 20,000 रुपए अदा करे। साथ ही मंच ने परिवाद व्यय के रूप में 2000 रुपए भी देने को कहा है। *(रा.प., 10.01.11)*

खास समाचार

उपभोक्ता संगठनों से विभाग करेगा संवाद

राज्य में खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हर माह के तीसरे गुरुवार को उपभोक्ता संगठनों से संवाद करेगा। इस दौरान उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव नियमित संवाद कर उनकी समस्याएं व सुझाव जानेंगे।

इन सुझावों व समस्याओं के आधार पर ही भविष्य के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है तथा खाद्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। *(रा.प., 22.02.11)*

प्रदेश भर में मिलेगा फोर्टिफाइड आटा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जनहित एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में सभी जगह लोगों को फोर्टिफाइड आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। आटे में पोषण के लिए अलग से फोलिक एसिड़, आयरन व अन्य विटामिन का मिश्रण किया गया है।

उन्होंने बताया कि कोटा को छोड़कर सभी संभागीय मुख्यालयों पर आटे का वितरण शुरू किया जा चुका है। कोटा में भी निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही वितरण शुरू हो जाएगा। आटे की गुणवत्ता बेहतर रहे इसके लिए निजी प्रयोगशालाओं में भी इसकी जांच कराई जा सकती है। *(रा.प. एवं दै.भा., 15.03.11)*

जिला स्तर के साझीदारों की उन्मुखीकरण कार्यशाला व उपभोक्ता सर्वेक्षण

कट्स द्वारा संचालित 'ग्रेनिर्क' परियोजना के तहत सभी 12 जिलों के परियोजना साझीदारों की दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला 16 व 17 मार्च को जयपुर में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य परियोजना के पिछले सालों की गतिविधियों का आकलन करते हुए उनकी सफलता का मूल्यांकन व उस पर आपसी चर्चा करना था, जिससे कि इस वर्ष होने वाली गतिविधियों में पिछली कमियों को दूर किया जा सके। उक्त मूल्याकंन कुल गतिविधियों तथा जिला स्तर पर की गई गतिविधियों के आधार पर किया गया व प्रत्येक साझीदार से उसकी प्रतिक्रिया जानी गई।

इसके अलावा इस वर्ष की प्रथम गतिविधि के रूप में किए जाने वाले उपभोक्ता सर्वेक्षण की प्रक्रिया पर भी गहनता से विचार-विमर्श किया गया। उन्मुखीकरण के दौरान ही साझीदारों को पैरवी, उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ, संचरण कला, सूचना प्रौद्योगिकी व प्रशिक्षण तथा फण्ड रेजिंग की मूल जानकारियों पर सत्र आयोजित किया गया। अन्त में इस साल आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

स्त्रोतः रा. प.: राजस्थान पत्रिका, दै. भा.: दैनिक भास्कर, न. नु.: नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।